2009:डीएचसी:3557-डीबी

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 21 जुलाई, 2009

निर्णय पारित: 31 अगस्त, 2009

आपराधिक अपील सं. 12/1997

रमेश कुमार उर्फ़ महेशी और अन्य ....**याचिकाकर्ता**

द्वारा: सुश्री सीमा गुलाटी अपीलकर्ता सं.1 की अधिवक्ता।

सुश्री मीना चौधरी शर्मा, अपीलकर्ता सं.2 की अधिवक्ता

बनाम

दिल्ली राज्य .....**प्रत्यर्थी**

द्वारा श्री एम.एन. दुदेजा, अति.लो.अभि.

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल
माननीय न्यायमूर्ति श्री अजीत भरिहोक

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हां

2. रिपोर्टर के पास भेजा जाना है या नहीं? हां

3. क्या निर्णय की सूचना डाइजेस्ट में दी जानी चाहिए? हां

अजीत भरिहोक, न्या.

1. अपीलार्थी रमेश कुमार उर्फ महेशी और राज कुमार उर्फ राजू को मृतक कमल की हत्या करने के लिए भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ सहपठित भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक को 2000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माने का भुगतान न करने पर क्रमशः छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने की सजा भी दी गई है।

2. संक्षेप में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 30.04.1994 को 11 बजे अपराह्न को मृतक कमल का अपनी मां शकुंतला देवी के साथ शिकायतकर्ता बबलू के तम्बू के सामने गर्म भोजन परोसने के मुद्दे पर बहस हो रही थी। अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी अपने तम्बू से बाहर आया और मृतक को फटकार लगाते हुए कहा "क्या तूने खाप खाना मचाया हुआ है"। उन्होंने गालियाँ देना भी शुरू कर दिया और शिकायतकर्ता की पत्नी के चरित्र के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की। मृतक ने उससे जाने का अनुरोध किया लेकिन अपीलकर्ता रमेश गाली देता रहा। अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ राजू भी झगड़े में शामिल हो गया और मृतक के बालों को पकड़ लिया। जबकि शिकायतकर्ता बबलू अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ा, अपीलकर्ता रमेश उर्फ महेशी ने अपने तंबू से एक बोतल निकाली और उसे तोड़ने के बाद, उसने मृतक कमल को छाती के नीचे बाईं ओर टूटी हुई बोतल घोंप दिया। दोनों याचिकाकर्ता घटनास्थल से फरार हो गए। घायल कमल को नरेंदर के तिपहिया स्कूटर से अग्रसेन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

3. अभि.सा.3 बलदेव राज ने पुलिस को जानकारी दी। यह पुलिस स्टेशन पश्चिम विहार में दिनांक 30.04.1994 को डी.डी. सं. 27ए के रूप में दर्ज किया गया था। डी.डी. रिपोर्ट की

प्रति की सत्यापन के लिए उप.नि. राम चंदर को भेज गया। वह अभि.सा.2 अश्विनी कुमार को साथ लेकर सी-256, राहत शिविर, पीरागढ़ी गया और पाया कि यह घटना सी-82, राहत शिविर, पीरागढ़ी के पास हुई थी। फिर, वह घटनास्थल पर गया लेकिन वहाँ कोई चश्मदीद गवाह उपलब्ध नहीं था। उन्हें पता चला कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वह अग्रसेन अस्पताल गया और पाया कि उसको मृतक घोषित कर दिया गया। अस्पताल में कोई चश्मदीद गवाह उपलब्ध नहीं था, इसलिए, वह घटनास्थल पर वापस आया, जहां वह शिकायतकर्ता बबलू से मिला और प्र.अभि.सा.6/ए में उसका बयान दर्ज किया और औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन भेज दिया।

4. उप.नि. राम चंदर ने फ़र्द मकबूज़गी प्र.अभि.सा. 2/ए. और अभि.सा.18/डी के तहत शिकायतकर्ता के तंबू के सामने से और अभि.सा. नरेंद्र के तंबू के सामने से खून से सनी मिट्टी और नमूना मिट्टी को जब्त कर लिया। उन्होंने गवाहों का बयान दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की व्यवस्था की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.अभि.सा. 9/ए में दर्ज की। उन्होंने जब्त सामग्री को सी.एफ.एस.एल. के लिए भी भेजा और सी.एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्राप्त की।

5. अपीलकर्ता रमेश कुमार को उसी दिन शिकायतकर्ता अभि.सा. 6 बबलू की निशानदेही पर उप.नि. राम चंदर ने मंगोलपुरी फ्लाईओवर से गिरफ्तार किया था। अपीलकर्ता राजू का तब तक पता नहीं चल सका जब तक कि उसने 03.07.1994 को न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। जाँच पूरा होने पर, अपीलार्थियों को भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ सहपठित भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए विचारण के लिए भेजा गया।

6. दोनों अपीलार्थियों पर तदनुसार आरोप लगाया गया था। उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और विचारण करने का दावा किया।

7. विचारण के समापन पर, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभि.सा.8 शकुंतला देवी की गवाही पर भरोसा करते हुए दोनों अपीलार्थियों को भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ सहपठित भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई।

8. अपीलार्थी नं.1 रमेश कुमार उर्फ महेशी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री सीमा गुलाटी और अपीलार्थी नं.2 राज कुमार उर्फ राजू की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मीना चौधरी शर्मा ने लगभग सामान तर्क दिया है। उनकी निवेदन दोगुनी है। सबसे पहले, यह तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभि.सा.8 शकुंतला देवी की अपुष्ट गवाही पर भरोसा करके गलती की है, जिनकी विश्वसनीयता नीचे चर्चा किए गए विभिन्न विरोधाभासों और अदृढ़ताओं के कारण संदिग्ध है। दूसरा, यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटना बिना किसी पूर्व-विचार के पल भर में हुई थी और अपराध का हथियार एक टूटी हुई कांच की बोतल है, इसलिए न तो मृतक को मारने का कोई आशय हो सकता था और न ही अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी को पता था कि उसका कृत्य इतना खतरनाक था कि उसकी मौत हो सकती थी।

इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी, आरोपी रमेश कुमार उर्फ महेशी द्वारा किया गया अपराध भा.दं.सं. की धारा 300 में अपवाद 4 को आकर्षित करता है और भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय गैर-इरादतन

हत्या, हत्या नहीं की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अभियुक्त राज कुमार उर्फ राजू की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, अभियुक्त राज कुमार उर्फ राजू की ओर से मृतक को बोतल घोंपने के आशय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि भा.दं.सं. की धारा 34 की मदद से धारा 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि कानूनी रूप से गलत है।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अभि.सा.8 शकुंतला देवी एक स्वाभाविक गवाह हैं जिनकी मौके पर उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घटना गर्म भोजन परोसने के संबंध में उनके और मृतक के बीच गरमागरम बहस के साथ शुरू हुई थी और यह कि उनके पास अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाने और असली अपराधी को मुक्त करने का कोई कारण नहीं था। इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ सहपठित धारा 302 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया है।

10. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों और अभिलेख पर की सामग्री पर विचार किया है।

11. अभि.सा.8 शकुंतला देवी की गवाही की विश्वसनीयता के लिए पहली चुनौती यह है कि घटनास्थल पर अभि.सा.8 शकुंतला देवी की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है क्योंकि अभि.सा.1 नरेंद्र कुमार, जो मृतक को तिपहिया स्कूटर से अस्पताल ले गए थे, ने यह नहीं कहा कि अभि.सा.8 शकुंतला देवी मृतक के साथ अस्पताल गई थीं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अगर शकुंतला देवी मृतक के साथ अस्पताल गई, तो उनका नाम एम.एल.सी., प्र.अभि.सा.11/ए में लाए गए कॉलम में उल्लेखित होना चाहिए था, जो कि नहीं है।

12. हम उपरोक्त प्रस्तुतिकरण से प्रभावित नहीं हैं। जहाँ तक तर्क के पहले भाग का संबंध है, यह मामले के तथ्यों के खिलाफ है। अभि.सा.1 नरेंद्र कुमार की गवाही के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि घायल कमल की मां उसके पिता और भाई ने उनसे घायलों को अस्पताल ले जाने का अनुरोध किया था और उन्होंने यह भी कहा है कि वे सभी अस्पताल जाने के लिए घायलों के साथ स्कूटर पर बैठे थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की मां अभि.सा.8 शकुंतला देवी वास्तव में उनके साथ अस्पताल गई थीं। मृतक के पिता अभि.सा.5 किशन लाल ने भी प्रतिपरीक्षा में यह कहते हुए इस तथ्य की पुष्टि की है कि उनकी पत्नी भी उनके साथ अस्पताल गई थी। एम.एल.सी. में शकुंतला देवी के नाम का उल्लेख न करने का कोई मतलब नहीं है। एम.एल.सी. तैयार करते समय, संबंधित डॉक्टर को मृतक के साथ आए प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए, किसी भी एक व्यक्ति के नाम का उल्लेख करना पर्याप्त है जो मृतक को अस्पताल ले गया था। इस प्रकार, हम कुछ भी गलत नहीं पाते हैं यदि डॉक्टर ने शिकायतकर्ता बबलू के नाम का उल्लेख केवल एम.एल.सी. प्र.अभि.सा.11/ए में इस उद्देश्य के लिए बने कॉलम में किया है। इस प्रकार, हमें मौके पर अभि.सा.8 शकुंतला देवी की उपस्थिति पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

13. अपीलार्थियों की ओर से अगला निवेदन यह है कि अभि.सा.8 की गवाही विश्वास को प्रेरित नहीं करती है क्योंकि उसने अभियोजन मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर खुद का खंडन किया है और न्यायालय में दिया गया उनका बयान मामले की जांच के दौरान धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत दिए गए उनके अपने बयान के विपरीत है। तर्क का विस्तार करते हुए, यह बताया गया है कि अभि.सा.8 शकुंतला देवी ने न्यायालय में गवाही दी है कि

जब उनके बेटे कमल को अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी ने मारा था, तो वह अभि.सा.3 बलदेव राज के घर गई और उसे बताया कि उसके बेटे को महेशी ने एक टूटी हुई कांच की बोतल से मारा है और उससे पुलिस को बुलाने का अनुरोध किया, जो दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत उनके बयान में सुधार है, कि उसने बलदेव राज को बताया कि उसके घर पर लड़ाई चल रही थी और उससे पुलिस को बुलाने का अनुरोध किया। यह आगे बताया गया है कि गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में शुरू में कहा था कि उसके बेटे बबलू और बहू बीणा ने घटना को नहीं देखा था क्योंकि वे तम्बू के अंदर थे, जबकि प्रतिपरीक्षा के बाद के हिस्से में उसने स्वीकार किया था कि उसने दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत अपने बयान में पुलिस को बताया था कि अपीलकर्ता द्वारा मृतक पर हमला करने के बाद, अपीलकर्ता ने बबलू पर हमला करने की कोशिश की, जो पीछे हटकर खुद को बचाने में कामयाब रहा और उसने यह भी बयान दिया कि उसने जांच के दौरान पुलिस को बताया था कि बबलू कमल को बचाने आया था। यह भी बताया गया है कि अपने मुख्य परिक्षण में गवाह ने कहा है कि अपीलकर्ता राज कुमार ने उनके बेटे कमल का बाल पकड़ लिया और अपीलकर्ता महेशी ने कांच की बोतल तोड़ने के बाद उनके बेटे को टूटी हुई बोतल घोंप दिया, जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने अपना बयान बदल दिया और कहा कि अपीलकर्ता महेशी ने अपने तंबू से टूटी हुई बोतल लाया था। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने हमसे आग्रह किया है कि हम उपरोक्त विरोधाभास के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि अभि.सा.8 शकुंतला देवी ने घटना को नहीं देखा है या कम से कम उनका कथन विश्वसनीय नहीं है।

14. हमें इस विवाद में कोई दम नहीं दिखता है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए विरोधाभास अप्रासंगिक हैं। साक्ष्य का मूल्यांकन करके कानून अच्छी तरह से तय किया गया है। साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए न्यायालय से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह

बाल की खाल निकाले और गवाह द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को अर्थ दे। गवाह की गवाही को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र संदर्भ में समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यदि, विश्लेषण पर गवाही स्वाभाविक और सत्य प्रतीत होती है, तो इसे केवल कुछ मामूली विरोधाभासों के कारण इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो समय बीतने के कारण स्मृति के कमजोर हो जाने के कारण सच्चे गवाह की गवाही में घटित हो सकती है। अभि.सा.8 शकुंतला देवी की गवाही पर समग्र रूप से विचार करने पर, यह सच प्रतीत होता है। अतः हम अपीलार्थियों के तर्क में कोई तथ्य नहीं पाते हैं।

15. अपीलकर्ता की ओर से अगला निवेदन यह है कि अभि.सा.8 शकुंतला देवी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक को उसके द्वारा भोजन परोसा गया था और वह उस समय खा रहा था जब घटना हुई थी। अभि.सा.8 शकुंतला, रुक्का प्र.अभि.सा.7/ए और एम.एल.सी. प्र.अभि.सा.11/ए की गवाही के अनुसार, बुरी तरह से घायल कमल को लेकर अपराह्न 11.55 पर अग्रसेन अस्पताल पहुंची और वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.अभि.सा.11/सी में भी मृत्यु का समय अपराह्न 11.55 दिया गया है। यह बताया गया है कि डॉ. के.एल. बरुआ (अभि.सा.9) ने अपनी गवाही में कहा है कि शव परीक्षण में उन्हें मृतक के पेट में अर्ध-पचा हुआ भोजन मिला और उन्होंने यह भी कहा कि भोजन को आंशिक रूप से पचने में सामान्य रूप से लगभग एक से चार घंटे लगते हैं। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, यदि मृतक घटना के समय, अर्थात, यानी अपराह्न 11.00 पर भोजन कर रहा था और उसकी मृत्यु अपराह्न 11.00 से अपराह्न 11.55 के बीच किसी समय हुई थी, तो उन्होंने जो भोजन लिया था वह आंशिक रूप से नहीं पच सकता था, इसलिए, घटना के कारण के बारे में

अभि.सा.8 का विवरण संदिग्ध है और अभियोजन पक्ष की पूरी नींव गिर गई। इसलिए, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने हमसे यह निष्कर्ष निकालने का आग्रह किया है कि अभि.सा.8 शकुंतला एक गढ़ा हुआ गवाह है।

16. हमारे विचार में, तर्क गलत है और साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ने पर आधारित है। अभि.सा.8 शकुंतला देवी ने अपनी गवाही में कहीं भी यह नहीं कहा है कि घटना के समय उनका बेटा खाना खा रहा था।

17. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि इस मामले में जाँच अनुचित और दागदार रही है। सबसे पहले, यह प्रस्तुत किया जाता है कि शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.अभि.सा.9/ए के अवलोकन से पता चलता है कि संबंधित डॉक्टर ने शव परीक्षण रिपोर्ट के साथ दस्तावेज़ के विवरण का उल्लेख नहीं किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि न तो संबंधित डॉक्टर और न ही जांच अधिकारी ने इस मामले में कोई स्पष्टीकरण दिया है। मृत्यु रिपोर्ट प्र.अभि.सा.18/एम के अवलोकन से भी पता चलता है कि रिपोर्ट में अपीलकर्ता या घटना के गवाह का कोई विवरण नहीं दिया गया है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। मृत्यु रिपोर्ट प्र.अभि.सा.18/ एम के अवलोकन से पता चलता है कि यह एक मुद्रित प्रपत्र पर टाइप किया गया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण कॉलम भरे गए हैं और इस प्रपत्र में हमलावर या गवाह के नाम के बारे में कोई कॉलम नहीं है। यह बताया जा सकता है कि मृत शरीर की पहचान करने वाले व्यक्तियों के नाम, अर्थात्, अभि.सा.6 बबलू, अभि.सा.7 बीना का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा, हमारे विचार में, संबंधित डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रमाणित कर दिया है। यदि अपीलकर्ता शव की प्राप्ति के समय और उसके साथ आए दस्तावेजों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे, तो वे प्रतिपरीक्षा में

अभि.सा.9 डॉ. एल.के. बरुआ या जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग सकते थे। उन्होंने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना है, इसलिए अब अपीलार्थियों को इस मामूली विसंगति को मुद्दा बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

18. आगे यह तर्क दिया गया है कि यह विलंबित प्राथमिकी का मामला है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि रुक्का प्र.अभि.सा.7/ए पर पुलिस का पृष्ठांकन यह दर्शाता है कि घटना 30.04.1994 को अपराह्न 11.00 बजे हुई थी और रुक्का को पुलिस स्टेशन भेजने का समय 01.05.1994 को पूर्वाह्न 2.50 बजे है। घटना के समय से चार घंटे के अंतराल के बाद अपराह्न 3.10 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इतनी लंबी देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए, हेरफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम इस तर्क में तथ्य नहीं पाते हैं। प्राथमिकी दर्ज करने में चार घंटे की देरी का कोई महत्व नहीं है, विशेष रूप से तब, जब पुलिस स्टेशन में प्राप्त प्रारंभिक जानकारी में घटनास्थल का गलत वर्णन किया गया था और उसके बाद जब जांच अधिकारी डी.डी. सं. 27ए में उल्लिखित घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्हें कोई गवाह नहीं मिला क्योंकि वे घायलों के साथ अस्पताल गए थे, जब वह अस्पताल पहुंचे थे, तो गवाह वहां से चले गए थे और उन्हें घटनास्थल पर वापस आना पड़ा था जहां उन्होंने अभि.सा.7 बबलू का बयान दर्ज किया था। उपरोक्त को करने में स्पष्ट रूप से कुछ समय लगा होगा, इसलिए, देरी को ठीक से समझाया गया है और अभि.सा.8 शकुंतला की गवाही पर संदेह करने का कारण प्रदान नहीं करता है।

19. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि अभि.सा.8 शकुंतला देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उनके बेटे बबलू का तम्बू उनके तम्बू से अलग है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि मुख्य जाँच में, अभि.सा.8 शकुंतला देवी ने घटना के बारे में गवाही देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि "मेरा बेटा हमारे तम्बू के बाहर खाट पर बैठा था। मैंने उसे खाना दिया और कमल को खाना खाने के लिए कहा। मैं उसके साथ खाट पर बैठा था। रमेश अपने तम्बू से बाहर आया क्योंकि वह हमारे पड़ोस में रहता था", जिसका अर्थ है कि यह घटना उसके तम्बू के सामने हुई थी जो उसके बेटे बबलू के तम्बू से अलग थी, जो कि रफ साइट प्लान प्र.अभि.सा.18/सी और स्केल्ड साइट प्लान प्र.अभि.सा.12/ए से गलत है, जिसमें बबलू के तम्बू के सामने घटनास्थल दिखाया गया है। इससे, अपीलकर्ताओं ने हमसे यह निष्कर्ष निकालने का आग्रह किया है कि मौके पर अभि.सा.8 शकुंतला देवी की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है और उनका बयान विश्वसनीय नहीं है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। घटनास्थल का वर्णन करने के लिए गवाह द्वारा उपयोग किए गए शब्द "हमारे तम्बू के सामने" थे। एक माँ के लिए अपने बेटों के घर को "हमारा घर" कहना अस्वाभाविक नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि माँ एक अलग घर में रह रही है। इसलिए, हमारे विचार में, यह विसंगति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि गवाह की अन्यथा विश्वसनीय गवाही को खारिज किया जा सके।

20. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि शव परीक्षण अभिलेख के अनुसार, मृतक के शरीर पर एक बनियान पड़ा था जिसे पुलिस ने जब्त नहीं किया है और उक्त बनियान को पेश न करने से अपीलकर्ताओं के बचाव में पूर्वाग्रह पैदा हुआ है क्योंकि बनियान में संबंधित कट के निशान अभियोजन पक्ष के मामले की शुद्धता या अन्यथा पर प्रकाश डाल सकते थे। आदर्श

रूप से, जांच अधिकारी को बनियान को जब्त कर लेना चाहिए था, लेकिन जांच अधिकारी की ओर से यह चूक किसी भी तरह से अभि.सा.8 शकुंतला देवी के अन्यथा विश्वसनीय और भरोसेमंद आँखों देखी बयान को त्यागने का आधार नहीं हो सकती है।

21. अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ राजू के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि भले ही अभियोजन पक्ष की कहानी को सच माना जाए, फिर भी अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ राजू ने अपने भाई रमेश कुमार उर्फ महेशी के साथ मृतक को टूटी हुई बोतल से चोट पहुंचाने का सामान्य आशय था। इस प्रकार, उनका निवेदन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ राजू को भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ सहपठित भा.दं.सं. की धारा 242 के तहत दोषी ठहराने के लिए भा.दं.सं. की धारा 34 को गलत तरीके से लागू किया है।

22. अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ राजू के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का मूल्यांकन करने के लिए, भा.दं.सं. की धारा 34 को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा, जो इस प्रकार हैः

"34. सामान्य आशय से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य।- जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब इसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन हैं मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

धारा 34 को पढ़ने से पता चलता है कि यह धारा कोई ठोस अपराध नहीं बनाती है। यह कानून का एक सिद्धांत निर्धारित करता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति पर हमले करते हैं तो वे उस व्यक्ति को हुई चोट के लिए उस हद तक जिम्मेदार हो जाते हैं, जिस हद तक कि उनका चोट पहुँचाने का सामान्य आशय था, भले ही संबंधित व्यक्ति या उसके सहयोगी द्वारा चोट लगी हो या नहीं। सामान्य आशय को या

तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है या इसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से एकत्र किया जा सकता है।

23. मौजूदा मामले में, साक्ष्य से जो तथ्य सामने आते हैं, वे यह हैं कि मृतक और उसकी माँ के बीच भोजन के संबंध में जोरदार बहस हुई थी, जिससे अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी नाराज हो गया और इसके परिणामस्वरूप विवाद हुई। अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ राजू, जो अपीलकर्ता रमेश कुमार का भाई है, भी आया और विवाद में शामिल हो गया और उसने मृतक के बालों को पकड़ लिया। इस बीच, अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी ने अचानक एक कांच का बोतल लाया, उसे तोड़ दिया और मृतक को घोंप दिया। इन तथ्यों से, जब अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ राजू और मृतक के बीच किसी भी पिछली दुश्मनी का कोई सबूत नहीं है, तो हमें यह अनुमान लगाना मुश्किल लगता है कि अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ राजू ने भी अपने भाई के साथ मृतक को टूटी हुई बोतल से वार करने का सामान्य आशय था। तथ्य यह है कि यह घटना अचानक से घटित हुई, अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ राजू और हमलावर रमेश कुमार उर्फ महेशी के बीच घटनास्थल पर सामान्य आशय के होने की किसी भी संभावना को खारिज करता है। इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी द्वारा बोतल घोंपने के कार्य के लिए भा.दं.सं. की धारा 34 की मदद से अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ राजू की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

24. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक को अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी ने अचानक हुए झगड़े में एक टूटी हुई कांच की बोतल घोंप दिया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मौजूदा

मामला भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है, वैसे तो भा.दं.सं. की धारा 303 के तहत दोषसिद्धि कानून में गलत है।

25. उपरोक्त याचिका को मूल्यांकन करने के लिए, हम संबंधित धारा को निकालना आवश्यक समझते हैं।

> "300. हत्या
>
> इसके बाद के मामलों को छोड़कर, गैर-इरादतन हत्या, हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, मृत्यु के आशय से किया गया है, या-
>
> ----
>
> ----
>
> ----
>
> अपवाद 4- गैर इरादतन हत्या, हत्या नहीं है अगर यह बिना किसी पूर्वचिन्तन के अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य कार्य किए बिना किया जाता है।"

26. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उसकी याचिका के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया है। विद्वान अधिवक्ता ने **थोलन बनाम तमिलनाडु राज्य**, 1984 एस.सी.सी. (आपराधिक) 164, पर भरोसा करके प्रस्तुत किया, कि जहाँ अचानक हुई लड़ाई में चाकू से किया गया एक भी वार भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II के अंतर्गत आता है, मौजूदा मामले की तरह अचानक लड़ाई जहाँ सिर पर एक ही प्रहार किया गया है, वही प्रावधान आमंत्रित करेगा। प्रासंगिक टिप्पणियों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें अपीलकर्ता ने शायद स्वयं अपने अहंकारी स्वभाव से गुमराह होकर आपत्ति जताई कि संपत ने उसे यह जगह छोड़ने के लिए क्यों कहा और इस हालात में उसने चाकू से एक वार किया जो मृतक की दाहिनी ओर छाती पर लगा, जो जानलेवा साबित हुआ। क्या अपीलकर्ता के बारे में कहा जा सकता है कि उसने हत्या की है? दूसरे शब्दों में, चाहे वह धारा 300 का भाग I हो या भाग III, भा.दं.सं. इस मामले के तथ्यों में आकर्षित होगी। यहां तक कि तमिलनाडु राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री रंगम भी बहुत गंभीरता से यह तर्क नहीं दे सके कि अपीलकर्ता का उद्देश्य संपत की हत्या करना था। उनका निवेदन था कि किसी भी दशा में जब अपीलकर्ता ने चाकू जैसे हथियार का उपयोग किया और शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से, छाती पर प्रहार किया, तो उसका आशय उस विशेष चोट को करना था और यह चोट चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा निष्पक्ष रूप से घातक पाई गई और इसलिए धारा 300 के भाग III को आकर्षित करता है। इस पहलू पर, निर्णय अनेकों हैं और केवल ज्ञात ज्ञान की निरर्थक प्रदर्शन को यहां दोहराना आवश्यक नहीं है। कोई भी लाभप्रद रूप से जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य, रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, कुलवंत राय बनाम पंजाब राज्य और हरि राम बनाम हरियाणा राज्य का उल्लेख कर सकता है। इस सूची में दो और मामले जोड़े जा सकते हैं-जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य और राम सुंदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इनमें से प्रत्येक निर्णय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि भले ही अपवाद I आकर्षित न हो, लेकिन अपेक्षित आशय का श्रेय अपीलकर्ता को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यहां जिन परिस्थितियों पर चर्चा की गई है, उसमें वह चाकू जैसे हथियार का प्रयोग किया था और इसलिए उसे इस ज्ञान के साथ जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि वह एक ऐसी चोट का कारण बन सकता था जिससे मौत होने की संभावना थी। ऐसी स्थिति में, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत अपराध करने का दोषी होगा। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 5 साल की सजा काफी पर्याप्त होगी।"

27. विद्वान अधिवक्ता ने रवींद्र शालिक नाइक और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2009 (2) पैरा 6 में स्केल 354 में संदर्भित भा.दं.सं. की धारा 300 के चौथे अपवाद के संबंध में स्पष्टीकरण का भी उल्लेख किया है:

> "6. भा.दं.सं की धारा 300 के चौथे अपवाद में अचानक लड़ाई में किए गए कार्यों को शामिल किया गया है। उक्त अपवाद अभियोजन के एक ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिन्तन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की गर्मी है जो पुरुषों के शांत कारणों को प्रभावित करती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करेंगे। अपवाद 4 में उत्तेजना है जैसा कि अपवाद 1 में है; लेकिन की गई चोट उस उत्तेजना का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें भले ही कोई कोई आघात पहुँचाया गया हो हो, या विवाद के मूल में कोई उकसावा हो या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें अपराध के संबंध में समान स्तर पर रखता है। 'अचानक लड़ाई' का अर्थ है आपसी उकसावा और दोनों पक्षों में मार-पीट होने से है। तब की गई हत्या का स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के कारण नहीं होती है, न ही ऐसे मामलों में पूरे दोष को एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा था, तो अधिक उचित रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होगा। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं होता है। लड़ाई अचानक होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को कमोबेश दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने आचरण से बढ़ाया नहीं होता तो यह उतना गंभीर रूप नहीं लेता जितना इसने लिया। फिर आपसी उकसावा और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक लड़नेवाले पर लगे दोष को विभाजित करना मुश्किल होता है। अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) पूर्व-चिंतन के बिना, (ख)

अचानक लड़ाई में; (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (घ) मारे गए व्यक्ति के साथ लड़ाई अवश्य हुई होगी। किसी मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' भा.दं.सं. में परिभाषित नहीं है। लड़ाई करने में दो लोग लगते हैं। जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए समय नहीं मिले और इस मामले में, पक्ष शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण क्रोधित हो गए हैं। लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भिड़न्त है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम बताना संभव नहीं है। यह तथ्य का सवाल है और कि झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 को लागु करने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्व विचारित नहीं था। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'अनुचित लाभ'। धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य (2003) (5) सुप्रीम 223, प्रकाश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2004) (11) एस.सी.सी. 381, बायवरापू राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, (2007) (11) एस.सी.सी. 218 और बुड्डू खान बनाम उत्तराखंड राज्य वि.अनु.या.(आप.) सं. 6109/08 का निपटान 12.1.2009 पर किया गया, में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।"

28. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित शब्दों में भा.दं.सं. की धारा 300 के तहत परिभाषित गैर इरादतन हत्या की तुलना में हत्या के अपराध के बीच अंतर करने के लिए **पप्पु बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 2009 (4) स्केल 521 का उल्लेख किया हैः-

"7. यह हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है कि कौन सा उचित प्रावधान लागू किया जाना था। भा.दं.सं. की योजना में गैर-इरादतन हत्या जीनस है और 'हत्या' इसकी प्रजाति है। सभी 'हत्या' 'गैर-इरादतन हत्या' है, लेकिन इसके विपरीत सभी 'गैर-इरादतन हत्या', 'हत्या' नहीं। आम तौर पर, हत्या की विशेष विशिष्टताओं के बिना 'गैर इरादतन हत्या' गैर इरादतन हत्या है जो हत्या के बराबर नहीं है। सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, भा.दं.सं. व्यावहारिक रूप से गैर-इरादतन हत्या के तीन श्रेणियों को मान्यता देता है। पहला है, जिसे 'प्रथम श्रेणी की गैर-इरादतन हत्या', कहा जा सकता है। यह गैर इरादतन हत्या का सबसे गंभीर रूप है, जिसे धारा 300 में 'हत्या' के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे को 'द्वितीय श्रेणी की गैर इरादतन हत्या' कहा जा सकता है। यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। इसके बाद, 'तृतीय श्रेणी की गैर-इरादतन हत्या' है। यह सबसे छोटे प्रकार की गैर-इरादतन हत्या है और इसके लिए दी जाने वाली सज़ा भी तीनों श्रेणियों के लिए दी गई सज़ाओं में सबसे कम है। इस श्रेणी की गैर-इरादतन हत्या धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।

8. 'हत्या' और 'गैर इरादतन हत्या' के बीच के शैक्षणिक अंतर ने हमेशा न्यायालयों को परेशान किया है। यदि न्यायालय इन धाराओं में विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के सही दायरे और अर्थ को खो देते हैं, तो वे खुद को सूक्ष्म अमूर्तता में खींचने की अनुमति देते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। इन प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए दृष्टिकोण का सबसे सुरक्षित तरीका धारा 299 और 300 के विभिन्न धाराओं में उपयोग किए गए मुख्य शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना प्रतीत होता है। निम्नलिखित तुलनात्मक तालिका दोनों अपराधों के बीच के अंतर के बिंदुओं को समझने में सहायक होगी।

धारा 299	कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करता है, यदि वह कार्य जिसके कारण मृत्यु हो जाती है-

धारा 300	कुछ अपवादों के अधीन गैर इरादतन हत्या, हत्या है यदि वह कार्य जिसके कारण मृत्यु हो जाती है
आशय	
(क) के आशय से जिसके कारण मृत्यु हो जाती है; या	(1) के आशय से जो मृत्यु का कारण बनता है; या;
(ख) ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का आशय जिससे मृत्यु होने की संभावना हो; या	(2) ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का आशय, जिसके बारे में अपराधी जानता है कि इससे उस व्यक्ति की मौत होने की संभावना है, जिसे नुकसान पहुँचाया गया है; या
	(3) के आशय से किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाना और पहुंचाई गई शारीरिक चोट सामान्य प्रकृति-क्रम में मृत्यु का कारण बनती है; या
ज्ञान	
* * * *	
(ग) इस ज्ञान के साथ कि इस कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।	4) इस ज्ञान के साथ कि यह कृत्य इतना खतरनाक है कि इससे मृत्यु होने की पूरी संभावना है या या ऐसी शारीरिक चोट जिसके

> कारण मृत्यु होने की संभावना हो; और ऐसा जोखिम उठाना जिसके कारण मृत्यु हो जाती है या ऐसी चोट जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है।"

29. उपरोक्त संदर्भित मामले में, आरोपी और मृतक के बीच गरमागरम बहस के परिणामस्वरूप गोली चलाई गई, जिसके परिणामस्वरूप मृतक के सीने पर चोट लगी, जिसे भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II के तहत आठ साल की हिरासत की सजा के साथ दोषसिद्धि के लिए उपयुक्त मामला माना गया।

30. हमारे विचार में, उपरोक्त कानूनी सिद्धांत, वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है, जो कि तकरार में टूटे हुए कांच की बोतल से किए गए एक ही वार करने का मामला है। अपीलार्थी और मृतक के बीच पिछली प्रतिद्वंद्विता या शत्रुता का कोई सबूत नहीं है। झगड़ा एक मामूली कारण से हुई, अर्थात अपीलकर्ता और उसकी माँ के बीच जोरदार बहस के कारण अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी को झुंझलाहट हुई, जिसके परिणामस्वरूप उसने एक बोतल लाई, उसे तोड़ा और क्षणिक उत्तेजना में मृतक को घोंप दिया। चूँकि अपीलकर्ता की ओर से किसी भी पूर्व-विचार या मकसद का कोई सबूत नहीं है, मामला पूरी तरह से भा.दं.सं. की धारा 300 के चौथे अपवाद के तहत आता है। इस प्रकार, अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी भा.दं.सं. की धारा 304 के भाग II के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है, न कि भा.दं.सं. की धारा 305 के तहत। अभियुक्त राज कुमार उर्फ राजू के संबंध में, हम पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी द्वारा किए गए कार्य के लिए उसे भा.दं.सं. की धारा 34 की मदद से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

31. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ राजू को भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ सहपठित धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को रद्द करते हैं। तदनुसार, उन्हें बरी किया जाता है।

32. जहाँ तक अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी का संबंध है, भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ सहपठित धारा 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि को भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II के तहत दोषसिद्धि में परिवर्तित कर दिया गया है और हम अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा देते हैं जो मामले में दिए गए तथ्यों में पर्याप्त है। आक्षेपित निर्णय और सजा पर आदेश के संदर्भ में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा और जुर्माना, तदनुसार, संशोधित है।

33. अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है। अभिलेख पर प्रस्तुत नामावली के अनुसार, अपीलकर्ता रमेश कुमार उर्फ महेशी पहले ही 04 वर्ष 10 महीने और 11 दिनों की अवधि की कारावास की सजा काट चुका है, इसके अलावा उसने 08 महीने और 07 दिनों की अवधि के लिए कुल छूट उपार्जित की है। इस प्रकार, उसने उसे दी गई सजा की अवधि पूरी कर ली है।

34. दोनों याचिकाकर्ता जमानत पर हैं। उनके संबंधित जमानतपत्र और प्रतिभूति बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और आरोपमुक्त किया जाता है ।

अजीत भरीहोक, न्या.

31 अगस्त, 2009 संजय किशन कौल, न्या.

पीएसटी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*